

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]	दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5, 2014/चैत्र 15, 1936	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 4
No. 5]	DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 2014/CHAITRA 15, 1936	[N.C.T.D. No. 4

भाग—II—I
PART—II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी
अधिसूचनाएं
दिल्ली, 5 अप्रैल, 2014

फा. सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(32)/2014/22621.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है :-

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2014

सं.3/4/आई.डी./2014/एसडीआर-खण्ड-I—(1) यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) तथा 49ट(2)(ख) में यह निर्दिष्ट है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने पर ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा

6. यतः, देश में पंजीकृत निर्वाचकों में से 97% से अधिक निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं,

7. यतः, आयोग ने यह आदेश दिया है कि "प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची" मतदाताओं को बांटी जाएगी,

8. अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि एक साथ होने वाले लोक सभा, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडीशा एवं सिक्किम के राज्य विधान सभा साधारण निर्वाचनों तथा 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन, जो कि 13-03-2014, 14-03-2014, 15-03-2014, 19-03-2014, 29-03-2014, 02-04-2014, 12-04-2014 तथा 17-04-2014 को अधिसूचित किए गए/किए जाने वाले हैं, सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:—

- I. पासपोर्ट
- II. डाइविंग लाइसेंस
- III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- IV. बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक

- V. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- VI. आधार कार्ड
- VII. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)
- VIII. मनरेगा जॉब कार्ड
- IX. श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- X. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, एवं
- XI. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. ऊपर पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,
आशीष चक्रवर्ती, सचिव

आदेश से,
बी. के. परचुरे, अवर सचिव (चुनाव)

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

NOTIFICATIONS

Delhi, the 5th April, 2014

No. CEO/COE/102 (32)/2014/ 22621.—The following is published for general information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 2nd April, 2014

No. 3/4/ID/2014/SDR-Vol. I.— (1) Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of

Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card has been issued to more than 97% registered electors in the country; and

7. Whereas, the Commission has directed that 'Authenticated Photo Voters Slip' shall be distributed to the electors.

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for General Elections to the House of the People, 2014 and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and bye-elections from 27 Assembly Constituencies being held simultaneously, which have been notified/to be notified on 13-03-2014, 14-03-2014, 15-03-2014, 19-03-2014, 29-03-2014, 02-04-2014, 12-04-2014 and 17-04-2014, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity :—

- (i) Passport;
- (ii) Driving License;
- (iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;
- (iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;
- (v) PAN Card;
- (vi) Aadhar Card;
- (vii) Smart Card issued by RGI under NPR;
- (viii) MNREGA Job Card;
- (ix) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;
- (x) Pension document with photograph; and
- (xi) Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery.

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By Order,
ASHISH CHAKRABORTY, Secy.

By Order,
B. K. PARCHURE, Under Secy. (Elections)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अप्रैल, 2014

फा. सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(33)/2014/22702.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2014

सं. 576/एकजट/2014/एसडीआर-खण्ड-I—(1) यतः, लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम के विधान सभा-2014 के साधारण निर्वाचनों और

बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2014, के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/10/13/2014; 10 मार्च, 2014 के सं. ईसीआई/पीएन/13/2014 और 27 मार्च, 2014 के सं. ईसीआई/पीएन/10/17/2014 के द्वारा कर दी गई थी;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, 07 अप्रैल, 2014 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे तथा 12 मई, 2014 (सोमवार) को अपराह्न 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान लोकसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम-2014 की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचनों, जो कि लोकसभा साधारण निर्वाचनों के साथ-साथ आयोजित होंगे, के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

आशीष चक्रवर्ती, सचिव

आदेश से,

बी. के. परचुरे, अवर सचिव (चुनाव)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th April, 2014

No. CEO/COE/102 (33)/2014/ 22702.—The following is published for general information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2014

No. 576/Exit/2014/SDR-Vol. I —(1) Whereas, the schedules for the General Elections to the House of the People, 2014 and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2014 and bye-elections in the State Legislative Assemblies of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal- were announced by the Commission vide Press Notes bearing No. ECI/PN/10/2014, dated 5th March, 2014. No. ECI/PN/13/2014 dated 10th March, 2014 & No. ECI/PN/17/2014 27th March, 2014;

1558 DG/14-2

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 AM on 07th April 2014 (Monday) and 06.30 PM on 12th May, 2014 (Monday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the House of the People, 2014 and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2014 and bye-elections from assembly constituencies in the State Legislative Assemblies of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal to be held simultaneously with the general election to Lok Sabha shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with aforesaid General elections and bye-elections.

By Order,

ASHISH CHAKRABORTY, Secretary

By Order,

B.K. PARCHUR, Under Secy. (Elections)